



# दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित



**4** सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं : जूली

**6** कश्मीर पर अमेरिका का बदलता रुख

**7** फिल्मों ने सिखाया अनजान चीजों से डरना नहीं : कियारा आडवाणी

## फर्स्ट टेक

### चीन की कम्पनी 'एवरग्रांडे' के संस्थापक को उम्रकैद की सजा

हांगकांग/एपी। चीन की संकटग्रस्त रीयल एस्टेट कंपनी 'एवरग्रांडे' के संस्थापक हुई का यान को बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उनकी कंपनियों पर दो अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। दक्षिणी चीन के शेनजेन शहर की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया। वर्ष 2020 में जब चीनी अधिकारियों ने रियल एस्टेट क्षेत्र में अत्यधिक कर्ज लेने पर रोक लगाई, तब एवरग्रांडे कंपनी पर 300 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की देनदारियां थीं और वह कंगाल हो गई थी। इस फैसले को एवरग्रांडे मामले में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। शेनजेन शहर की एक अदालत ने 67 वर्षीय हुई (जिन्हें यू जियायित भी कहा जाता है) और उनकी कंपनी 'एवरग्रांडे' को बहुत बड़े आर्थिक घोटाले का दोषी पाया है।

### अमेरिकी राजदूत पहली लड़ाख यात्रा पर पहुंचे

लेह/भाषा। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने लड़ाख की अपनी पहली यात्रा के दौरान बृहस्पतिवार को संगम में जंरकार और सिंधु नदियों के संगम स्थल पर रिवर राफ्टिंग की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गोर के लड़ाख दौरे का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के अग्नू प्राकृतिक परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करना था। अमेरिकी राजदूत बुधवार को श्रीनगर पहुंचे थे जहां उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके आवास पर मुलाकात की। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की।

### 'समाधान समारोह' यह सुनिश्चित करने का प्रयास कि दोनों पक्षों को लगे कि उनकी जीत हुई : सूर्यकांत

नई दिल्ली/भाषा। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की 'समाधान समारोह' पहल का उद्देश्य लंबित मामलों का मध्यस्थता के जरिए इस तरह समाधान करना है कि दोनों पक्षों को यह महसूस हो कि उनकी जीत हुई है। उच्चतम न्यायालय के 'समाधान समारोह' के तहत मामलों के लंबित रहने की समस्या से निपटने के लिए मध्यस्थता और विवादों के सहमति से समाधान के अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पहल के जरिए पक्षकारों को आपसी सहमति से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में मदद की जाती है।

## भारत-जापान ने समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किया समझौता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सैन्य सहयोग में तालमेल बढ़ाने का संकल्प लिया। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके जापानी समकक्ष शिंजिरो कोइजुमी के बीच हुई वार्ता में दोनों नेताओं ने नौवहन और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी भी एकतरफा कार्रवाई तथा बल या दबाव के जरिए यथास्थिति बदलने के प्रयासों का कड़ा



विरोध किया।

दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि राजनाथ और कोइजुमी ने मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थापना के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बयान में कहा गया, दोनों मंत्रियों ने बढते वैश्विक तनाव के दौर में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा माहौल के आकलन को साझा करने के महत्व पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि वे नौवहन और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा में बाधा डालने वाली किसी भी एकतरफा कार्रवाई तथा बल या दबाव के जरिए यथास्थिति बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं। यह टिप्पणी चीन की ओर संकेत के

रूप में देखी जा रही है, क्योंकि भारत और जापान दक्षिण चीन सागर तथा पूर्वी चीन सागर में बीजिंग की आक्रामक सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंतित हैं।

दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन' (एमओए) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक रुपरेखा उपलब्ध कराएगा। इस समझौते के तहत जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच सहयोग को मजबूत किया जाएगा। इसमें समुद्री क्षेत्र की जागरूकता से जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान और खोज एवं बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना शामिल है। राजनाथ और कोइजुमी ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को ठोस रूप देने के लिए तेजी से कदम उठाने पर सहमति जताई।

## बचाव

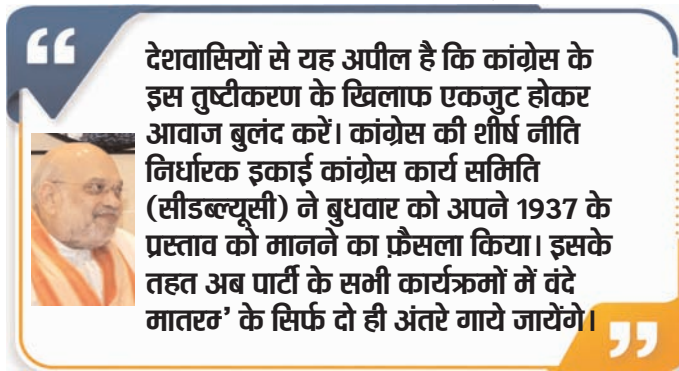


उत्तराखंड के धारचूला में तावाघाट के पास कुलागाड पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद भारतीय सेना के कुमाऊं रकाउट्स के जवानों ने बचाव अभियान चलाया और फंसे हुए 300 से अधिक स्थानीय लोगों व पर्यटकों की मदद की।

## 'वंदे मातरम्' के केवल दो अंतरे गाने का कांग्रेस का फैसला 'राष्ट्रविरोधी' : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

चेन्नई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 'वंदे मातरम्' के केवल दो अंतरे गाने का पार्टी का फैसला 'राष्ट्र-विरोधी' है तथा इसका मकसद कानून की खुली अवहेलना कर 'वोट बैंक' के लिए तुष्टीकरण करना है। शाह ने राष्ट्रगीत को पूरा गाने के बजाय केवल दो अंतरे गाने के कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के फैसले का उल्लेख करते हुए देश के विभाजन के इतिहास का जिक्र किया और कहा कि 'वंदे मातरम्' के टुकड़े करने के कारण देश को इसके परिणाम भुगतने पड़े। शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स'



देशवासियों से यह अपील है कि कांग्रेस के इस तुष्टीकरण के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने बुधवार को अपने 1937 के प्रस्ताव को मानने का फैसला किया। इसके तहत अब पार्टी के सभी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम्' के सिर्फ दो ही अंतरे गाये जायेंगे।

पर कहा, "कांग्रेस कार्यसमिति ने 'वंदे मातरम्' के पूर्ण गान की जगह केवल दो अंतरे गाने का जो फैसला किया है, वह न केवल देश विरोधी है बल्कि संसद के बनाए कानून की खुली अवहेलना भी है।" शाह

ने एक्स' पर कहा, "कांग्रेस ने ही 1937 में तुष्टीकरण के लिए 'वंदे मातरम्' के दो टुकड़े किए। वहीं से दो-राष्ट्र सिद्धांत को ताकत मिली और देश का विभाजन हुआ।" उन्होंने कहा, 'वंदे मातरम्' के 150वें वर्ष

पर (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी (के नेतृत्व वाली) सरकार ने यह ऐतिहासिक गलती सुधारी और पूर्ण गान को कानूनी स्वरूप दिया लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर उसी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम्' के टुकड़े करने की गलती एक बार हो चुकी है और देश उसके परिणाम भुगत चुका है। उन्होंने कहा, "देशवासियों से यह अपील है कि कांग्रेस के इस तुष्टीकरण के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें।" कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने बुधवार को अपने 1937 के प्रस्ताव को मानने का फैसला किया। इसके तहत अब पार्टी के सभी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम्' के सिर्फ दो ही अंतरे गाये जायेंगे।

## रुस के मिसाइल हमले में कीव में 14 लोगों की मौत, 33 अन्य घायल

कीव/एपी। रुस ने रातभर यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में कई मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि कई घंटे चले इस हवाई हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है। रुस की सेना ने हाल के महीनों में कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं। इसका एक मुख्य कारण

यूक्रेन के पास अमेरिका निर्मित पेंडियाट हवाई रक्षा मिसाइलों की लगातार हो रही कमी है। यूक्रेन के पास यह एकमात्र ऐसा हथियार है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने विभिन्न देशों से और अधिक पेंडियाट मिसाइलें भेजने की अपील की है। हालांकि, ईरान युद्ध और रुस के खिलाफ यूक्रेन की चार

## मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए

ढाका/भाषा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बृहस्पतिवार को देश के नये राष्ट्रपति चुने गए। देश में इस पद के लिए 35 साल में पहली बार हुए मुकाबले में 78 वर्षीय आलमगीर ने 255 मत प्राप्त किये। मुख्य निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन अधिकारी ए.एम.एम. नासिर उद्दीन ने कहा कि बीएनपी के वरिष्ठ नेता ने अपने प्रतिद्वंद्वी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष एवं जमात-



ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11-दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद को हरा दिया। उन्होंने कहा कि आलमगीर को 255 मत मिले, जबकि ओली अहमद को 88 मत प्राप्त हुए।

## महात्मा गांधी की पांडुलिपि रिकॉर्ड 16.2 करोड़ रु में बिकी

नई दिल्ली/भाषा। महात्मा गांधी के अपने करीबी सहयोगी और स्वतंत्रता सेनानी आनंद टी. हिंगोरानी को लिखे गए 688 ऑटोग्राफ वाले विचारों (जिनमें सत्य, अहिंसा और सेवा जैसे विषय शामिल थे) के संग्रह को सैफ्रनआर्ट की नीलामी में 16.20 करोड़ रुपये में बेचा गया। यह नीलामी में बिके किसी भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेज के लिए एक विश्व रिकॉर्ड है। हिंगोरानी की पत्नी विद्या के निधन के बाद दो साल तक मार्गदर्शन, चिंतन और हौसला बढ़ाने वाले रोजाना हाथ से लिखे संदेशों को बाद में अर्थ ऑफ द डे नाम की किताब में संकलित किया गया। ये संदेश दोनों के बीच हुए पत्राचार के सबसे निजी और सुरक्षित बचे हुए दस्तावेजों में से एक हैं।

'गांधी : फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ आनंद टी. हिंगोरानी' नाम की नीलामी में गांधी से जुड़ी चिट्ठियों, पांडुलिपियों, तस्वीरों और निजी चीजों के 86 खंड शामिल थे। नीलाम करने वाली संस्था के अनुसार, इन पांडुलिपि में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह (सांसारिक वस्तुओं या धन के प्रति मोह न रखना), निर्भयता, धार्मिक समानता, अस्पृश्यता निवारण,

## शीर्ष अदालत ने इमरान खान को अस्पताल भेजने के आदेश पर सरकार की पुनर्विचार याचिका लौटाई

इस्लामाबाद/लाहौर/भाषा। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजने के अपने आदेश में संशोधन के अनुरोध वाली सरकार की पुनर्विचार याचिका बृहस्पतिवार को लौटा दी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को निर्देश दिया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 73 वर्षीय संस्थापक को अगले दो दिन के भीतर इस्लामाबाद के 'शिफा इंटरनेशनल अस्पताल' ले जाया जाए और 16 सितंबर के लिए निर्धारित अगली सुनवाई तक उन्हें वहीं रखा जाए।

सरकार ने पहले कहा था कि वह अदालत के आदेश को लागू करेगी, लेकिन बाद में शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर आदेश पर पुनर्विचार और उसे वापस लेने का अनुरोध किया। खबरों के अनुसार, अदालत के रजिस्ट्रार कार्यालय ने कागजात का पूरा संकलन नहीं होने का हवाला देते हुए सरकार की याचिका लौटा दी। सूत्रों ने बताया कि सरकार खामियों को दूर करने और जरूरी बदलाव करने के बाद नई याचिका दायर कर सकती है। हालांकि, 'पीटीआई' के महासचिव



सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपत्तियां उठाए जाने के बाद सरकार ने पुनर्विचार याचिका वापस ले ली। उन्होंने कहा, 18 अगस्त के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन न करने का कोई बहाना नहीं है। इमरान खान साहब को तत्काल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। आज ही यह दिन है। न्यायमूर्ति शाहिद बहीद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अंतिम निर्देश जारी किए थे और सरकार को अस्पताल भेजने की समयसीमा बृहस्पतिवार आधी रात को समाप्त हो जाएगी।

खान की पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें बृहस्पतिवार रात 11 बजकर 59 निमट तक अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया तो यह शुक्रवार को सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर करेगी।

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 21-07-2026<br>सूर्योदय<br>6:37 बजे           | 22-08-2026<br>सूर्योदय<br>6:10 बजे |
| BSE<br>77,537.72<br>(+628.04)                | NSE<br>24,231.85<br>(+153.55)      |
| सोना<br>16,404 रु.<br>(24 कैरेट) प्रति ग्राम | चांदी<br>245,266 रु.<br>प्रति किलो |

## मिशान मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी पत्रिका  
epaper.dakshinbharat.com



केलाहा मण्डेला, मो. 9828233434

## जाहिल लोगों

ये लौन लोका उड़या देंगे, हैं कौन कुछ कुछ तोलो। संसद तक पर हमला करते, हैं क्या मकसद यह खोलो तो। आखिर किसका यह देश कहां, कथनी करनी को तोलो तो। जाहिल लोगों कुछ पल को ही, अपनी औकात टटोलो तो।

## डीके शिवकुमार ने अमित शाह से अपर भद्रा परियोजना की प्रक्रिया तेज करने का आग्रह किया

चेन्नई/बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को चेन्नई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपर भद्रा परियोजना के लिए केंद्र द्वारा घोषित 5,300 करोड़ रुपये की राशि जल्द जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राशि जारी होने में देरी से परियोजना का काम प्रभावित हो रहा है। शिवकुमार ने यहां दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कर्नाटक की पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की घोषणा की थी लेकिन अब तक यह राशि जारी नहीं की गई।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, उन्होंने शाह से कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने

(बसवराज) बोम्मई सरकार के दौरान केंद्रीय बजट में अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। संसद में घोषणा किए जाने के बावजूद अब तक यह राशि आवंटित नहीं की गई

## अमित शाह की उपस्थिति में तमिलनाडु और पुडुचेरी के हितों की रक्षा का वचन दिया है मैंने : शिवकुमार

चेन्नई/बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में वचन दिया कि प्रस्तावित मेकेदातु बांध मामले में तमिलनाडु और पुडुचेरी के हितों की रक्षा की जाएगी। दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने के बाद शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पानी के बंटवारे से जुड़े मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए एक अलग बैठक का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की जरूरतों के लिए पांच अरब घन फुट पानी (टीएमसी) इस्तेमाल करने के अलावा, प्रस्तावित मेकेदातु बांध में जमा बाकी पानी तमिलनाडु के लिए होगा। उन्होंने तमिलनाडु और पुडुचेरी को संबोधित करते हुए कहा, "बांध हमारे लिए नहीं, बल्कि आपके लिए ही बनाया जायेगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "ये एक राज्य में कारोबार करते हैं और निवेश कहीं और करते हैं। हमारी प्राथमिकताएं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं। ऐसे में राज्य सरकार को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे राशि कहां और किस तरह खर्च करें।" मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, शाह ने शिवकुमार के सुझाव से आंशिक रूप से सहमति जताई और उन्हें सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के प्रमुखों के साथ बातचीत करने को कहा।

सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की राशि के इस्तेमाल की तरीके पर भी चिंता जताई। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी नीति या नियम बनाया जाना चाहिए, जिसके तहत राज्य सरकार स्थानीय जरूरतों के आधार पर सीएसआर की राशि के इस्तेमाल का फैसला कर सके।

मुख्यमंत्री ने कहा, "ये एक राज्य में कारोबार करते हैं और निवेश कहीं और करते हैं। हमारी प्राथमिकताएं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं। ऐसे में राज्य सरकार को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे राशि कहां और किस तरह खर्च करें।" मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, शाह ने शिवकुमार के सुझाव से आंशिक रूप से सहमति जताई और उन्हें सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के प्रमुखों के साथ बातचीत करने को कहा।



**वडोदरा/भावा** गुजरात के वडोदरा जिले में एक खड़ी बस के ऑटोमैटिक दरवाजे में फुलने से सफाई करीब बीस मिनट हो गई। पुलिस ने बस को रोककर वहाँ पर जाँच की। वहाँ पर एक युवा पतिवारा को यह जानकारी दी। पुलिस ने बस पर अभिषेक गुप्ता के अनुसार, यह सुखद घटना बुधवार शाम शहर के बाहरी इलाके में एकपुर्वीय थाणा क्षेत्र स्थित एक गैराज में हुई। अभिषेक ने बताया कि मुक्तक की पहचान दिव्येश अडवाला के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि गैराज के पास खेल रहा दिव्येश संभवतः खड़ी बस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अभिषेक बस का दरवाजा बंद हो गया और उसकी गर्दन उसमें फंस गई। उन्होंने बताया कि इसी सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि गैराज में मौजूद दो लोग दोनों ने बंद को बमाल के लिए बस को दूर धक्का दिया। बस को रोकने के बाद वहाँ पर जाँच की। लेकिन तब तक यह बेहोश हो नीचे गिर गया। पुलिस उपपुलक (डीसीपी) गुप्ता ने बताया कि बस को अस्पताल ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।



**चंडीगढ़/भाषा।** पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में शामिल नहीं होने की इजाजत दी थी क्योंकि उन्हें यहां पंजाब विश्वविद्यालय में एक परीक्षा में शामिल होना था।



**नई दिल्ली/भाषा।** दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में उपक्रैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। सफ़दरजंग अस्पताल के सूत्रों ने यह जानकारी दी। अस्पताल ने अभी उनकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पांच सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे में आग लगाए जाने से जुड़े मामले में 17 दिसंबर 2018 को उपक्रैद की सजा सुनाई थी। कुमार तिहाड़ जेल में बंद थे। दिल्ली की एक अदालत ने भी दंगों के दौरान दो सिखों की हत्या से जुड़े एक अन्य मामले में फरवरी 2025 में उन्हें उपक्रैद की सजा सुनाई थी। तीन बार लोकसभा क्षेत्र रहे कुमार ने बाहरी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और वह कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। उन्होंने 2018 में दोषी ठहराए जाने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

**नई दिल्ली/भाषा।** प्रकार तरण तेजपाल ने 2013 के यूनैस्जिउन मामले में दोषारिद्धि के खिलाफ बहिष्पत्तिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। बंबई उच्च न्यायालय के छह अगरस्त के आदेश के खिलाफ अधिवक्ता आदित्य साम्बाहरे के जरिये अपील दाखर की गई। इससे पहले, गोवा सरकार ने तहलका के पूर्व सपायक को सुनाई गई सजा बढ़ाने की मांग को लेकर शीर्ष न्यायालय का रुख किया था। सरकार का कहना था कि इस मामले में उन्नकैद की सजा दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ अदालत द्वारा पांच साल पहले तेजपाल को बरी करने के फैसले को पलट दिया था और उन्हें (तेजपाल को) दुष्कर्म की दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सहजीवन साथी (लिव इन रिलेशनशिप) के रूप में वयस्कों के बीच संबंध शादी जैसा ही है और न तो माता-पिता, न ही दोस्त उसकी पसंद में दखल दे सकते हैं। सहजीवनमूर्ति सौरभ बनर्जी ने सहजीवन साथी के रूप में रह रहे एक युवक को लड़की के परिवार की ओर से मिल रही धमकियों के बाद उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की। अदालत ने कहा कि वयस्क होने के नाते उन्हें अपनी पसंद के साथी के चयन और उसके साथ रहने का 'पूरा अधिकार' है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**नातपुत्र/भावा।** महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुरूपतिनारा को राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम्' के केवल दो अंतरे गाने के फेरसले को लेकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की तथा इसे संविधान के खिलाफ और विपक्षी दल की 'मानसिक गुलामी' का परिचायक बताया। फडणवीस ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से यह भी कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि 22 अप्रैल को पुणे में होने वाला राष्ट्र गान्धी की छात्रों की गुंज' कार्यक्रम सिर्फ कांग्रेस नेओं द्वारा

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चलाए जा रहे कॉलेजों के विद्यार्थियों तक ही सीमित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम खुली बातचीत के बजाय एकतरफा भाषण (मोनोलॉग) जैसा होगा। | इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने बुधवार को अपने 1937 के प्रस्ताव को मानने का फ़ैसला किया। इसके तहत अब पार्टी के सभी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम्' के सिर्फ़ दो ही अंतरे गाये जायेंगे। कांग्रेस |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

का यह फैसला वह आया जब भाजपा ने उसके नेताओं पर पार्टी कार्यक्रमों में राष्ट्रपति का पूरा संस्कारण न गाकर उसका अपमान करने का आरोप लगाया। इस फैसले के बारे में पूरे जाने पर फडणवीस ने कहा कि ऐसा फैसला संविधान के खिलाफ है, क्योंकि भारत अब ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की संसद के फैसलों का संवैधानिक प्रभुत्व होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “और अगर हम स्वयंभू भारत की संसद द्वारा लिए गए निर्णय का पालन नहीं करते हैं, तो हम गुलामी की परंपरा को जित्ना रखेंगे।” भाजपा नेता फडणवीस नेता ने आरोप लगाया, “हम हमेशा कहा करते थे कि यह मानसिक गुलामी भी।

इस फैसले से उन्होंने हमारे आरोपों अपनी मानसिक गुलामी साबित संविधान का विरोध, दोनों ही बातें जाहिर कर दी हैं।” निषेध के नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गुंज’ कार्यक्रम के तहत छात्रों से बाच्यवृत्ति करने के लिए पूरे आने पर फडणवीस ने कहा, लेकिन अगर यह सभी के साथ खुली बातचीत होती तो हमें खुशी होती। मेरी जानकारी की मुताबिक, “वही कांग्रेस नेताओं द्वारा चलाए जा रहे कॉलेजों में पंजीकृत विद्यार्थी से बाच्यवृत्ति करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं: वे (विद्यार्थी) भी हमारे ही हैं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि कलू विलाकर, यह कार्यक्रम अगर नियंत्रित माहौल में आयोजित किया जाएगा।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

मेसूर। कर्नाटक में चामराजनगर जिले के शिलुवेपुरा नन क्षेत्र में कथित रूप से उपद्रवियों द्वारा लगाई गई आग से करीब 10 एकड़ जंगल प्रभावित हुआ है। नन विभागे के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। वन घटना एक शिकार रोहो शिक के विस्फोट से नह किए जाने के कुछ दिन बाद हुई है। नन अधिकारियों को आशंका है कि 15 अगस्त को चामराजनगर में तीन कथित शिकारियों की मौत के बाद उपद्रवियों ने गुरसे में इस आगजनी को अंजाम दिया।

अधिकारियों ने बताया कि आग शिलुबेपुरा नव क्षेत्र में फैल गई, जिससे करीब 10 एकड़ इलाका प्रभावित हुआ। इसके अलावा जंगरी के पास स्थित एक शिकार रोधी शिविर भी नष्ट हो गया। यह घटना चामराजनगर स्थित कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में कई शिकार रोधी शिविरों को कथित तौर पर विस्फोटकों से उड़ाए जाने के बाद सामने आई है। ये घटनाएं 15 अगस्त को कथित मठभेड़ में

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

बंगलूर। कावेरी बेसिन, खासकर मांझा में किसानों ने कृष्णा राजा सारार (केआरएस) बांध से तिलनालछोड़े के तेल पानी छोड़े जाने के विरोध में बृहस्पतिवार को प्रदर्शन तेज कर दिया। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के उस सिफारिश को बरकरार रखा है, जिसमें 12 अगस्त से 15 दिनों तक प्रतिदिन 12,00,000 क्यूबिक पानी छोड़ने की बात कही गई थी। सूत्रों के अनुसार, तिलनालछोड़ा सरकार ने उद्यतन न्यायवादी का रुख किया है और कर्नाटक को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश का पालन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

मंड्या के संजय चौराहे पर किसानों ने धरना दिया। कन्नड़ सेना के कार्यकर्ताओं ने किसानों के इस प्रदर्शन को समर्थन देते हुए पुराने बेंगलूरू-मैसूरु राजमार्ग को जाम कर दिया। प्राश्नकारियों ने दावा किया कि बांध में पानी का स्तर महज 109 फुट है। उन्होंने सवाल उठाया कि इसके बावजूद तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का फैसला क्यों किया गया।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कज़ड़ कार्यकर्ता वाटल नागराज ने पूरे देश में इसका मजबूत संकेत देने के लिए कर्नाटक के लोगों से एकजुट होकर आंदोलन का समर्थन करने की अपील की। मंड्या के विधायक रवि कुमार गोड़ा (गनिया) ने तमिलनाडु के लिए पानी छोड़े जाने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। कावेरी सिंचाई सलाहकार समिति की बुधवार को हुई बैठक में गोड़ा ने सवाल उठाया कि किसानों के किसानों को सिंचाई

पानी से कैसे यचित किया जा सकता है। उन्होंने कहा, एक तरफ आप तमिलनाडु के एक पानी छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें पानी नहीं देंगे। अगर हमारे किसानों को उनकी फसलों के लिए पानी नहीं दिया गया तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उनका कहना था कि राज्य में पिछले दशकों में पहली बार इतना भीषण और अभूतपूर्व सूखा पड़ा है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु में दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष कावेरी जल विवाद का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर मेकेदातु में संतुलन जलाशय बनाने की गोरदार पैरवी की।

बीदर। कर्नाटक के बीदर में एक इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद विद्यार्थियों द्वारा 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे लगाए जाने पर कथित रूप से आपत्ति जताने के लिए प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, 'एक छात्र के पिता की शिकायत के

आधार पर चित्तगुप्ता थाने में 17 अगस्त को अब्दुल हकीम (39) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता का बेटा चित्तगुप्ता कस्बा स्थित इंटर कॉलेज में 12वीं कक्षा का छात्र है। प्राथमिकी में बताया गया कि कॉलेज में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह

योजित किया गया था और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम व राष्ट्रगान हुआ। गणतन्त्र दिवस के अनुसार, पूर्वाह्न करीब 10 बजे राष्ट्रगान के बाद छात्र कुछ अन्य विद्यार्थियों के साथ कॉलेज परिसर से बाहर निकल रहा था और इस दौरान उन्होंने 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' जैसे नारे लगाए।

**नई दिल्ली/भाषा।** दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार की शिकायत अपील समिति (जीएसी) को निर्देश दिया कि वह शिरडी साईबाबा को निशाना बनाने वाले कथित रूप से भड़काने और आपत्तिकायक युद्धबू वीडियो को हटाने की मांग वाली शिकायत पर विचार करे। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) और गूगल को नोटिस जारी कर इस संबंध में नया आवेदन दाखिल करने वाले 'श्री साईबाबा संस्थान न्यास, शिरडी' की याचिका पर जवाब मांगा है।

इससे पहले उक्त न्यायालय ने जीएसी को सात दिनों के भीतर आपतिजनक वीडियो हटाने के मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। बृहत्पतिवार को सुनाई गई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि जीएसी ने 13 अप्रैल को ही एक आदेश पारित कर ऐसे वीडियो और लेखों को हटाने का निर्देश दे दिया है। हालांकि, याचिकाकर्ता न्याय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद दुबे और अधिवक्ता प्राची दुबे ने दलील दी कि आपतिजनक सामग्री को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है और कुछ वीडियो तथा लेख अब भी इंटरनेट पर मौजूद हैं।

**बेंगलूरु/दक्षिण भारत।** इतिहास बार-बार इस बात का गवाह रहा है कि व्यक्ति प्रगति तभी संभव होती है, जब व्यक्ति अपनेपन तथा युक्तिकरण के डर को पीछे छोड़कर सकारात्मक बदला की दिशा में कदम बढ़ाता है। जीवन में प्रभाव पैदा करने के लिए पहल करना बेहद जरूरी है। अवसरों को ठुकराने से सफलता की संभावना समाप्त हो जाती है, जबकि आगे बढ़कर प्रयास करने से कम से कम बदलाव लाने का अवसर जरूर मिलता है। इसलिए युवाओं को चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए साहस, संवेदनसंपन्न के साथ समाज पर सकारात्मक प्रभाव प्रयास करना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर सिंधी कांजोजे के प्राध्यापक डॉ. राजे ने व्यक्त किया। वे राष्ट्रीय (सीनूटू डी वी यू) घटक संस्थान निरंतर टिच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2026-27 शैक्षणिक एमबीए, एमसीए एवं पाठ्यक्रमों के नए विषय आयोजित करेंगे।

**जानमोनी दास गिरफ्तार**

**कोझिकोड/भाषा।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके परिवार को खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 'टाइमजेंडर मेमोरण्डम ऑटिस्ट' और 'शोशल मीडिया इम्प्लूयर्स' जानमोनी दास को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, कोझिकोड साइबर पुलिस ने दास और शोशल मीडिया पर उक्त कथित वीडियो सामान करने वाले दो अन्य लोगों को तलाब किया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि थाने में मामले में सबूत जुटाने और पुष्टता सहित अन्य प्रमाणित जारी हैं। यह मामला भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नय्या हर्ददास की ओर से 27 जुलाई को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, दास ने नीट प्रभाव लोक को खिलाफ हुए प्रश्नों के सिलसिले में कथित तौर पर ये टिप्पणियां की थीं। इन टिप्पणियों से संबंधित वीडियो शोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ था। टिप्पणियों को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद दास ने एक वीडियो जारी करके माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि भाषा की जानकारी नहीं होने के कारण उससे ये टिप्पणियां हुई हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

लिप तैयार है। उन्होंने कहा कि नए बांध के डिजाइन, स्थान और प्रयोग निर्माण का जिम्मा तमिलनाडु संभालेगा जबकि इसका पूरा खर्च केरलम वहन करेगा। तमिलनाडु लगातार कहता रहा है कि पुराना बांध सुरक्षित है, जबकि केरलम ने उसका का कहना है कि यह असुरक्षित है और जलस्तर अधिक होने की स्थिति में यदि बांध टूटता है तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जान को खतरा हो सकता है। केरलम ने पुराने बांध का उपयोग बंद किए जाने की मांग की है। तमिलनाडु ने अपनी सरकार की 'मिशन सफ़ुद्र' परियोजना, खान पान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में हाल में किए गए संशोधनों को वापस लेने की जरूरत तथा सदन की सदस्य संख्या बढ़ाए बिना संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने की आवश्यकता का मामला भी उठाया।

करलम नए  
लनाडु को  
नी देने के  
बिना संसद में महिलाओं के लिए  
एक-तिहाई आरक्षण लागू करने की  
आवश्यकता का मामला भी उठाया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**दिल्ली/भाषा।** कथित ठग उजागर व  
प्रदेशखेर ने बृहस्पतिवार को जेल सही दि  
मी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम 2021-  
गार्टी (आप) के संयोजक अरविंद साबित ह  
ल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मामले के  
लिखकर "तीन और बड़े बोर्ड" का

का खुलासा करने की। पत्र में कहा गया है, 'गोपाल जी, सर्वेन्द्र जी और मैं', आपके भ्रष्टाचारों को खोपने के लिए एक और कदम। मैं आगे बढ़ रहे हूँ। मैं किफात खुलासे सही हूँ। अब 'शराब नीति' का दावा अगला नंबर 'जल' और भी तीन और मामले

बाकी हैं, और अब ये उजागर होंगे। इसमें कहा गया है, आपके 'तीन और' 'भूषाचार' का तीन अन्य महत्वपूर्ण विभागों में जल्द ही खुलना किया जाएगा, 'चिंता मत कीजिए। जल्द ही आप' 'एनीटाइम, ऑनलेज पार्टी ऑफ़ के रूप में' की पहचान होलागी की पार्टी के रूप में और मजबूत होलागी।'

प्र में कहा गया है, 'पंजाब के लोगों को फिर से बेवकूफ बनाने भूल जाइए; जनता आप सभी के सबक सिखा देने वाली है। जैसा कि हुआ, वैसा ही पंजाब में भी होगा।' की जनता आपके अहंकार और घोटालेजना पार्टी को इससे भी तरीके से नकार देगी। इसमें कहा कि केजरीवाल के प्रॉक्सि ब्राह्म युवाओं या 'जेन की' को झड़वा वाल काफ नही करेगी और सुकें

भी अन्य चीज से पहले पूर्व मुख्यमंत्री का पदनिाश करेगा।

पत्र में कहा गया है, "मैं आपको एक संकेत देकर कुछ स्पष्ट कर दूँ-आप और आपके प्राँक्षी 'संस्थापक'। उम्मीद है, आपको 2015 और 2016 में मेरे साथ अपने जुड़ाव की याद होगी। हो सकता है कि आप लोगों को डेलुलुतु (भ्रम) हो, लेकिन मुझे सब याद है। मैं जल्द ही आपको चौकाऊंगा।"







# कांग्रेस विधायकों का विधानसभा के बाहर धरना, कार्यवाही में शामिल नहीं हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र बृहस्पतिवार को यहां शुरू हुआ जिसमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस विधायकों ने राज्य के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर कथित प्रतिबंध के मुद्दे को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर धरना दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विपक्षी सदस्यों की गैरमौजूदगी पर निराशा जताई और उनसे कार्यवाही में हिस्सा लेने की अपील की। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और विधायी कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने भी कार्यवाही में भाग नहीं लेने के लिए कांग्रेस विधायकों की आलोचना की।

कुछ विधायी काम निपटाने व शोकाभिव्यक्ति के बाद कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कांग्रेस विधायक बृहस्पतिवार की सुबह पोद्दार मूक-बधिर स्कूल पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश व मीडिया कवरेज पर कथित प्रतिबंध का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता और मीडिया को सरकारी स्कूलों की खराब हालत को उजागर करने से रोकने की कोशिश कर रही है। जूली ने कहा कि इस आदेश को वापस लिया जाए। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे के भी मांग की।

बाद में ये विधायक जूली की अगुवाई में पोद्दार स्कूल से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। जब विधायकों ने समूह में विधानसभा में जाने की कोशिश की तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई। कई नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। ये विधायक विधानसभा



के बाहर धरने पर बैठ गए।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के परिसर में प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना 'बाहरी लोगों' के प्रवेश पर रोक लगा दी है। साथ ही लिखित मंजूरी के बिना स्कूल की गतिविधियों की कोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई है। कांकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने हाल ही में घोषणा की थी कि उसकी टीम राज्य के उन स्कूलों का दौरा करेगी जिनकी हालत 'ठीक नहीं है'। इसके बाद ही राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रोक संबंधी यह आदेश निकाला। हालांकि, शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि इस

आदेश से आंगंतुकों पर पूरी तरह कोई रोक नहीं है। आज के धरना स्थल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि विधायकों को नियमित दरवाजे से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तथा दरवाजे पर ताला लगा दिया गया है। डोटासरा ने राज्य की भाजपा सरकार पर तानाशाही वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया और स्कूलों की हालत दिखाने पर लगाई गई रोक पर सवाल उठाए। डोटासरा ने आरोप लगाया कि विधानसभा के गेट नंबर छह पर ताला इसलिए लगाया गया था ताकि कांग्रेस विधायक शिक्षा विभाग में कथित भ्रष्टाचार, शिक्षा मंत्री

की कथित विफलता, कथित कृषि घोटाले और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कमियों जैसे मुद्दों को न उठा सके। उन्होंने कहा, 'सवालों से डरती, जवाबदेही से भागती... ये भाजपा की कैसी भगोड़ी सरकार है जो लोकतंत्र पर ताला लगाती है? विधायकों को सदन में प्रवेश से रोकना और लोकतंत्र के मंदिर पर ताला लगाना, भाजपा सरकार द्वारा सीधे-सीधे लोकतंत्र की हत्या करना है।' नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि विधानसभा सुचारु रूप से चले, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि विधायकों को उस दरवाजे से प्रवेश करने से क्यों रोका गया जिसका वे पारंपरिक रूप से इस्तेमाल करते रहे हैं। जूली ने पूछा, जब से विधानसभा बनी है, हम इसी दरवाजे से आते रहे हैं। आज इसे क्यों बंद किया गया? उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक पहले सुबह स्कूल गए जहां उन्हें एक नोटिस दिखाया गया जिसमें कहा गया था कि वे परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, फिर हम पैदल विधानसभा पहुंचे और हमें यहां प्रवेश करने से रोक दिया गया। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए एक 'आवाज दबाने वाला कानून' लेकर आई है और मांग की कि इस आदेश को वापस लिया जाए। राज्य के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि 3,768 स्कूलों को जर्जर घोषित किया गया था, लेकिन उनमें से किसी में भी पुनर्निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है।

उन्होंने आगे दावा किया कि लगभग 85,000 कक्ष खराब हालत में हैं और अध्यापकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं। कांग्रेस विधायकों के धरने में मौजूद पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा।

## राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, कांग्रेस विधायक शामिल नहीं हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र बृहस्पतिवार को यहां शुरू हुआ जिसमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने भाग नहीं लिया और राज्य के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर कथित प्रतिबंध का मुद्दा उठाया। जूली ने कहा कि इस आदेश को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के आंदोलन को दबाना चाहती है। बाद में ये विधायक जूली की अगुवाई में पोद्दार स्कूल से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। जब विधायकों ने समूह में विधानसभा में जाने की कोशिश की तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई। कई नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। ये विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि विधायकों को छह नंबर दरवाजे से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तथा दरवाजे पर ताला लगा दिया गया है।



## मुख्य सचिव ने पीएम गति शक्ति राज्य मास्टर प्लान की समीक्षा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में पीएम गति शक्ति राज्य मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा पीएम गति शक्ति पोर्टल पर जीआईएस आधारित डेटा अपलोड करने, डेटा लेयरों की मैपिंग एवं परियोजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पोर्टल पर उपलब्ध डेटा को अधिक उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सभी आवश्यक लेयरों की मैपिंग प्राथमिकता से पूरी की जाए। श्रीनिवास ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व भूमि की मैपिंग करते समय केवल भूमि का स्थान ही नहीं, बल्कि भूमि की किस्म सहित अन्य

महत्वपूर्ण संबंधित विवरण भी पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएं। इससे विभागों को अपनी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि चयन में सुविधा होगी तथा योजना अधिक प्रभावी ढंग से बनाई जा सकेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर प्राथमिकता से मैप किया जाए, ताकि परियोजनाओं की योजना बनाने समय विभिन्न विभागों के पास संबंधित क्षेत्र की समग्र एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहे। उन्होंने प्रदेश में संभावित इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप्स की पहचान, उनका विश्लेषण एवं मैपिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के डेटा को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराने से परियोजनाओं की आवश्यकता, उपलब्ध संसाधनों और कनेक्टिविटी से संबंधित कमियों की बेहतर पहचान की जा

सकेगी। बैठक में बताया गया कि राज्य के पीएम गति शक्ति पोर्टल पर केंद्र सरकार की 29 अनिवार्य लेयर्स तथा राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 23 अतिरिक्त लेयर्स की मैपिंग की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 11 अन्य लेयर्स भी मैप की गई हैं। इससे विभिन्न विभागों को परियोजनाओं की योजना एवं क्रियान्वयन के लिए एकीकृत भू-स्थानिक जानकारी उपलब्ध हो रही है। बैठक में पीएम गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान की प्रगति की भी जानकारी दी गई। इसके तहत बारां जिले द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है, जबकि धौलपुर, सिरौही, करौली एवं जैसलमेर जिलों में मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। जिला स्तर के मास्टर प्लान में स्कूल, अस्पताल, अस्पताल, विद्युत एवं सड़क सहित विभिन्न सामाजिक एवं बुनियादी सुविधाओं से संबंधित डेटा को शामिल किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पीएम

गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जीआईएस आधारित एकीकृत प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के डेटा को एक मंच पर उपलब्ध करार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समय एवं समन्वित योजना में सहायता करना है। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भू-स्थानिक डेटा, सेंटेलाइट इमेजरी और विभिन्न डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से परियोजनाओं की प्लानिंग, निगरानी, कनेक्टिविटी का आकलन तथा संभावित गैप्स की पहचान में सहायता मिलती है। बैठक में उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, नागरिक विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और गति शक्ति पोर्टल से जुड़े विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

## जयपुर में 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या, कंबल में बांधकर खाली जगह पर फेंका शव

जयपुर। जयपुर में 75 वर्षीय एक बुजुर्ग की कथित तौर पर हत्या कर शव को अन्यत्र फेंक दिने जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान टोडारामसिंह निवासी जगदीश के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि जगदीश का निर्वस्त्र शव सांगानेर सदर थानाक्षेत्र में एक खाली जगह पर कंबल में लिपटा मिला। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया आशंका है कि हत्या के बाद शव को वहां लाकर फेंका गया। सहायक पुलिस आयुक्त भवानी सिंह ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू की।

## पुलिस उपनिरीक्षक रिश्तव लेते गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बृहस्पतिवार को कोटपुतली में एक उपनिरीक्षक को 3,500 रुपये की कथित रिश्तव लेते रहे हाथ गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उनके अनुसार, पुलिस थाना कोटपुतली के उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह को रिश्तव मामले में गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो के एक बयान के अनुसार, परिव्रादी ने शिकायत दी थी कि उसके द्वारा बैंक के विरुद्ध अदालत के माध्यम से कोटपुतली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। परिव्रादी के अनुसार, आरोपी राजेंद्र सिंह इसके अनुसंधान अधिकारी हैं और वे आगे की कार्यवाही करने की एवज में पांच हजार रुपए मांग रहे हैं। शिकायत के संतुष्टापन के दौरान आरोपी ने रिश्तव मांगते हुए 1500 रुपए ले लिए।



## टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य के लिए स्क्रीनिंग, जांच और उपचार में लाएं तेजी : मुख्य सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्यपाल हरिभाऊ बागडे एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के प्रयासों को और गति दी जाए। इसके लिए स्क्रीनिंग, जांच और उपचार को सघन करते हुए कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा जिला स्तर पर प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव गुरुवार को शासन सचिवालय में टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने टीबी की समय पर पहचान के लिए एक्स-रे मशीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और न्यूक्लियर एसिड एंटीबिफेक्शन टेस्ट (छ-ड) बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की कार्यप्रणाली से सीख लेते हुए अन्य जिलों में भी प्रभावी कार्ययोजना के साथ परिणामों में सुधार लाया जाए।

श्रीनिवास ने टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (ब्रह्म) और डिफेंसिफ़ेड टीबी केयर पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीबी रोगी का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के साथ उसके परिवार के पात्र सदस्यों की स्क्रीनिंग और आवश्यकतानुसार प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने टीबी उन्मूलन में जनभागीदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने माय भारत स्वयंसेवकों को अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ने, एनसीसी कैडेट्स की ब्लॉक स्तर तक भागीदारी बढ़ाने तथा एनएम्, आशा सहयोगिनी और सीएचओ सहित जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार कर समयबद्ध रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्रीमती माधव्री राठौड़ ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अभियान की प्रगति की

जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में 29 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई थीं। यह संख्या वर्ष 2023 में बढ़कर 586, वर्ष 2024 में 3,350 तथा वर्ष 2025 में 6,547 तक पहुंच गई। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में 2 करोड़ 38 लाख 43 हजार 583 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है तथा टीबी रोगियों को 2 लाख 4 हजार 888 पोषण किट वितरित की गई हैं। वर्ष 2026 में एक्स-रे उपयोग लक्ष्य के मुकाबले 83 प्रतिशत तक पहुंचा है। श्रीमती राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में टीबी जांच के लिए 643 छ-ड लैब, 132 हेंड-हेल्ड एक्स-रे यूनिट और 652 फिक्स्ड एक्स-रे मशीनें उपलब्ध हैं। अभियान के दौरान 3 लाख 29 हजार से अधिक छ-ड टेस्ट और 35 लाख 87 हजार से अधिक एक्स-रे किए गए हैं। बैठक में एनएचएम के मिशन निदेशक डॉ. जोगा राम सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

## सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं : जूली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

जयपुर । राजस्थान में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर गुरुवार को राज्य सरकार के उस आदेश के खिलाफ विधानसभा तक विरोध मार्च निकाल लिया, जिसमें उन्होंने मीडिया पर शिक्षा विभाग की कवरेज करने पर रोक लगा दी। भजनलाल सरकार के आदेश के खिलाफ अब राज्य में मीडिया लोगों को यह नहीं बता पाएगी कि मौजूदा समय में स्कूल कितने जर्जर हो चुके हैं या शिक्षा प्रणाली कितनी बदहाल हो चुकी है। इसी फैसले के विरोध में टीकाराम जूली ने कांग्रेस के अन्य विधायकों के खिलाफ साथ मिलकर विधानसभा तक मार्च निकाला, जिसमें वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस दौरान दोनों

नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत भी की। टीकाराम जूली ने कहा कि ये लोग हमें कब तक रोकेंगे। ये लोग हमें नहीं रोक पाएंगे। मैं खुद विधानसभा में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि ये लोग हमें नहीं रोक पाएंगे। ये लोग बच्चों को रोकना चाहते हैं। ये लोग बच्चों की आवाज को दबाना चाहते हैं। हर घर में बच्चा है। आखिरकार आप कितने बच्चों को मोबाइल ले जाने से रोकेंगे। आप लोग कितने मीडिया वाले रोकने का काम करेंगे। हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। उन्होंने नवोदय विद्यालय खुलावाए थे। आज नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे देश दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इन लोगों ने एजुकेशन में एक भी काम किया हो, तो आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि हम आईटीई



लेकर आए थे। ये लोग अब उसका भगतान तक नहीं कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान और समय शिक्षा अभियान हम लोगों ने शुरू करने का काम किया था। लेकिन, अफसोस की बात है कि इन लोगों ने उसे भी बंद करने का काम किया। यही नहीं, सीएसआर का पैसा आरएसएस को दिया जा रहा है। मेरा यह कहना है कि यह पैसा स्कूलों को दीजिए। अगर यह पैसा स्कूलों को दिया गया होता, तो आज की तारीख में स्कूलों की तस्वीर बदल गई होती।

टीकाराम जूली ने कहा कि इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हम पहले ही साल में सारे पद भर देंगे। अफसोस की बात है कि अभी तक सवा लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि 9 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। 3768 स्कूल जर्जर हो चुके हैं। वहां स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। इन स्कूलों को 85 हजार क्लासरूम क्षतिग्रस्त हैं। स्कूल में कोई भी पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है और मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन, अफसोस की बात है कि इस दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा है। यह सभी भाजपा के पाप हैं और अब इन पापों को भरने के लिए बीजेपी की ओर से एक ढक्कन कानून लाया गया है। ऐसे ढक्कन कानून में अपनी जेब में लेकर चलाता हूँ। ये ढक्कन कानून अब चलने वाला

नहीं है। इस ढक्कन कानून को राजस्थान के बच्चे और जनता उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह फूटने, बल्कि ढंका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी पूरी फिल्म बाकी है। हम राजस्थान के सभी स्कूलों में जाकर यहां के स्कूलों की जर्जर हालत के बारे में लोगों को बताएंगे। हम इन लोगों को बताएंगे कि मौजूदा समय में स्कूलों की हालत कैसी बनी हुई है। यह छुपाएंगे, लेकिन हम दिखाएंगे। ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, लेकिन अब हम मुद्दों पर बात करेंगे और मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। वहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरा। उनके मुताबिक, यह सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है।

## विद्यार्थियों से जुड़ी शिकायतों की संवेदनशीलता से त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

जयपुर। साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग के निदेशक महेन्द्र कुमार खींची ने गुरुवार को राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग से संबंधित परिवारों की स्थिति, पोर्टल पर उनकी श्रेणीवार प्रविष्टि, शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया तथा लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान निदेशक खींची ने शिक्षा विभाग से संबंधित सभी श्रेणियों में प्राप्त परिवारों का विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने शिकायतों की प्रकृति, संबंधित विभागीय स्तर तथा निस्तारण की स्थिति की समीक्षा करते हुए

अधिकारियों को परिवारों के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खींची ने कहा कि प्राप्त शिकायतों को उनकी प्रकृति एवं विषय के अनुरूप सक्षम स्तर पर शीघ्र प्रेषित किया जाए, ताकि अनावश्यक विलंब न हो और परिवारियों को समयबद्ध राहत मिल सके। उन्होंने शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग के साथ निस्तारण की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि यदि किसी परिवार की वर्तमान श्रेणी उसके वास्तविक विषय से मेल नहीं खाती, तो आवश्यकतानुसार उसका री-कैटेगरीजेशन किया जाए, जिससे शिकायत संबंधित एवं सक्षम स्तर तक पहुंचकर उसका

उचित समाधान सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही परिवारों की सही श्रेणी निर्धारण की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों से संबंधित परिवारों का निस्तारण संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ किया जाए, ताकि संबंधित विद्यार्थियों को समय पर आवश्यक सहायता एवं समाधान उपलब्ध हो सके। इस दौरान बालिका सैनिक स्कूल से संबंधित प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा कर उनके निस्तारण की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया गया। निरीक्षण के दौरान खींची ने परिवार निस्तारण से जुड़े कार्मिकों से संवाद कर पोर्टल की कार्यप्रणाली एवं शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली।









## दक्षिण भारत राष्ट्रमत

### अद्भुत देश भारत!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय चुनाव प्रणाली की शक्ति एवं सामर्थ्य के बारे में की गई टिप्पणी के बाद ऐसे अनेक क्षेत्रों की चर्चा होना स्वाभाविक है, जिनमें भारत कई 'विकसित' देशों से बहुत आगे है। हमारे देश में साजिशान नकारात्मकता का बहुत प्रचार किया गया, इसलिए लोगों को इस बात पर आसानी से विश्वास नहीं होता है। भारत में कई लोगों को लगता है कि कथित विकसित देशों में हर कोई सुखी है, वहां सोना बरस रहा है और अपने देश की हर चीज खराब है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है। हर देश की अपनी समस्याएं हैं। अपनी तमाम समस्याओं के बावजूद, भारत खान-पान के मामले में स्वर्ग है। जितने पकवान यहां बनते हैं, उतने किसी देश में नहीं बनते हैं। यहां आज भी रोटी बहुत सस्ती है। फलों और सब्जियों का तो कहना ही क्या! गांवों-करबों में दस-बीस रुपए की ताजा सब्जी पूरा परिवार खा सकता है। ऐसा अमेरिका में संभव नहीं है। एक भारतीय नागरिक ने जापान में तरबूज का भाव पूछा तो हैरान रह गया। वहां एक मामूली तरबूज की कीमत भारतीय मुद्रा में लगभग एक हजार रुपए थी, जबकि उससे ज्यादा अच्छा तरबूज यहां बीस-तीस रुपए में बड़ी आसानी से मिल सकता है। गांवों में तो और सस्ता मिल सकता है। अमेरिका में एक किलो आलू की कीमत लगभग 200 रुपए है। भारत की सब्जी मंडियों में बीस-तीस रुपए किलो के भाव में अच्छे आलू मिल जाते हैं। अगर घर के किसी कोने में खाली जगह हो और वहां आठ-दस आलू यूं ही लगा दें तो धरती माता उन्हें कई गुना करके वापस देती है। ब्रिटेन में हरी सब्जियां बहुत महंगी बिकती हैं। अमरुदों के भाव बहुत ज्यादा होते हैं। वहीं, भारतीय मंडियां इन चीजों से भरी पड़ी हैं और कीमतें सामान्य हैं।

भारत में फरवरी के आखिर में जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है, कई लोग मौसम को कोसने लगते हैं। वे कहते हैं कि 'काश, हम किसी ठंडे मुल्क में पैदा होते तो बात ही कुछ और होती।' उन्हें एक बार रूस के याकुत्स्क का चक्कर लगाकर आना चाहिए। वहां माइनस पचास डिग्री से. तक तापमान चला जाता है। हर कहीं बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। सर्दियां बहुत कठोर होती हैं। गर्मियों की अवधि छोटी होती है, जिसमें आलू, गाजर, पत्तागोभी, चुकंदर जैसी गिनती की सब्जियां उगा सकते हैं। सर्दियों में सब्जियां दूसरे इलाकों से मंगानी पड़ती हैं, जो बहुत महंगी होती हैं। बाहर निकलने से पहले भारी-भरकम ऊनी कोट, दस्ताने, टोपी, जूते पहनने पड़ते हैं। अगर नहीं पहनेंगे तो शरीर का कोई हिस्सा सुन्न पड़ सकता है, जिसे बाद में हटाने की नौबत आ सकती है। एक पर्यटक का कान सुन्न पड़ गया था, जिसे तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी थी। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जिंदगीभर पछताते। भारत पर सूर्यदेव अपनी अपार कृपा बरसाते हैं। ठंडे देशों के लोग यहां आकर धूप सेकते हैं, ताकि तन-मन को थोड़ा सुकून मिले। अगर हमने इतनी धूप का सदुपयोग करने के लिए कोई तकनीक विकसित की होती तो आज ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होते। हमें एलपीजी सिलेंडरों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ता और हर साल अरबों डॉलर बचते सो अलग। भारत के तीज-त्योहार अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दीपावली पर दीपक, तेल और बाती से ही लाखों लोगों तक धन का प्रवाह हो जाता है। ऐसा अर्थशास्त्र कितने देशों के पास है? हमारे हर त्योहार का कोई-न-कोई वैज्ञानिक आधार जरूर होता है। हमें इन पर गर्व करना चाहिए। अगर हमारे नेता और अधिकारी गंभीरता एवं ईमानदारी से काम करें, जनता अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाए तो भारत सबसे समृद्ध और खुशहाल देश बन सकता है।

## ट्वीटर टॉक



कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 'वंदे मातरम' के पूरे गाने के बजाय सिर्फ दो लाइन गाने का फ़ैसला न सिर्फ देश विरोधी है, बल्कि पार्लियामेंट के बनाए कानून की खुली अवहेलना भी है।**इज़्ज़ 1937 में, तुष्टीकरण के लिए, कांग्रेस ने ही 'वंदे मातरम' को दो हिस्सों में बाँट दिया था।**

-अमित शाह

कांग्रेस ने हमेशा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को देश बनाने का एक जरूरी हिस्सा माना है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से लेकर 'प्रोजेक्ट टाइगर' तक और संविधान में आर्टिकल 48- और 51-(स) जोड़कर, नेचर की सुरक्षा को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूती बनाया।

-अशोक गहलोत



कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा 'वंदे मातरम' के केवल दो छंद गाने का निर्णय एक बार फिर उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर करता है। 1937 में भी कांग्रेस ने अपनी मूल भावना से समझौता किया था, और आज भी वही मानसिकता स्पष्ट है।

-भजनलाल शर्मा

## प्रेरक प्रसंग

### जीव का मूक प्रेम

महादेवी वर्मा एक बार मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती रही। इस दौरान उनकी पालतू गिलहरी गिज़ू, जिसे उन्होंने स्वयं मरणासन्न अवस्था से बचाकर पाला था, घर पर अकेली रह गई। जब भी महादेवी के कमरे का द्वार खोला जाता, गिज़ू अपने झूले से उतरकर तेज़ी से दोड़ती, किंतु द्वार पर किसी और को देखकर उसी तीव्रता से वापस अपने घोंसले में लौट जाती। घर के सभी लोग उसे प्रतिदिन उसका प्रिय भोजन काजू देने का प्रयास करते रहे। अस्पताल से लौटने पर जब महादेवी ने गिज़ू के झूले की सफाई की, तो उन्हें वहां काजू के दाने जमा मिले, लगभग अछूते। इससे यह प्रकट हुआ कि गिज़ू ने उन दिनों अपना प्रिय भोजन लगभग त्याग ही दिया था, मानो प्रतीक्षा और विरह में उसकी भूख ही पर गई हो। महादेवी लौटती तो गिज़ू अस्वरथ लेखिका के तकिए के पास बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को सहलाने लगी, ठीक किसी समर्पित परिचारिका की भांति।

बेंगलूरु | शुक्रवार | 21-08-2026



www.dakshinbharat.com



/dakshinbharat



/dakshinbharat

DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY

# कश्मीर पर अमेरिका का बदलता रुख

प्रमोद भार्गव

मोबाइल : 9981061100

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अपने पहले जम्मू-कश्मीर दौरे में यहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुला से मुलाकात के बाद कश्मीर को भारत का अभिन्न और अहम भू-भाग बताया। ताकि सुरक्षा के लिहाज से सराहना की। अमेरिकी राजदूत का यह बयान अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पर चौंका देने वाला होने के साथ अमेरिका और भारत के संबंधों में बदलाव का उल्लेखनीय संकेत है। लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका की स्थिति भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय विवाद के रूप में देखी जाती रही है। जिसे अक्सर भारतीय प्रशासन वाले कश्मीर जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता रहा है। ऐसे में एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक का यह दो टूक बयान कश्मीर की धरती पर देना इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर कश्मीर को लेकर भारत की अखंडता एवं संप्रभुता की पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है। इस बयान से पाकिस्तान को तो झटका लगा ही है, चीन भी सकंटे में है।

यह रहे अमेरिका ने वर्ष 2018 से ही जम्मू-कश्मीर के तात्कालिक पूर्वी लद्दाख और लेह को छोड़कर अपने नागरिकों को यात्रा नहीं करने की चेतावनी दी हुई है। इस नसीहत को चौथी श्रेणी में रखा हुआ है। गोर ने फिलहाल इस यात्रा चेतावनी को कम करने का कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि इस बिंदु पर अमेरिका यात्रा में छूट दे सकता है ? हालांकि उस समय धारा-370 बहाल थी और घाटी में आतंकी संकट की छाया छाई रहती थी। अगर 2019 में धारा-370 और 35-ए को भारत सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते विलोपित कर दिया, उसी के बाद से कश्मीर में सुरक्षा संबंधी हालातों में निरंतर सुधार हो रहे हैं और पत्थरबाजी व अन्य आतंकी घटनाओं में कमी आई है। पहलगाम में आतंकी हमले के एक दिन बाद ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उक्त चेतावनी की फिर से पुष्टि करते हुए नई एडवायजरी जारी कर दी थी। जो अभी भी लागू है। चूंकि गोर दक्षिण एशिया व मध्य एशियाई मामलों के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनकी कश्मीर यात्रा और दो टूक बयान की अपनी अलग अहमियत है। खासतौर



पर तब जब पाकिस्तान के संबंध भी अमेरिका के साथ फिलहाल मधुर बने हुए हैं और अमेरिका ईरान से लड़े जा रहे युद्ध में पाकिस्तान को अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस बयान से उमर अब्दुला को भी बड़ा झटका लगा है। क्योंकि वे कुछ दिनों से धारा-370 की पुर्नबहाली की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जून-2026 में द हिंदू हडल (अंग्रेजी समाचार पत्र) सत्र के दौरान कहा था कि 2019 में 370 को हटाना भारत सरकार की सबसे बड़ी नीतिगत भूल थी। साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और विशेष संवैधानिक अधिकारों की बहाली की भी मांग की थी।

पाकिस्तान धर्म की घुड़ौ पिलाकर 35 साल से भारत पर आतंकी हमले करता रहा है। जबकि उसे सबसे मुकम्मल उत्तर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया था। लेकिन वह बाज नहीं आ रहा है। कुत्ते की पूंछ की तरह पाक की पूंछ टेढ़ी ही बनी हुई है। गैर-कश्मीरियों और हिंदुओं की हत्या के लिए उसकी कूरता समाप्त नहीं हो रही है। जाहिर है, पाकिस्तान भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बदले को भूल गया है। उसे एक बार फिर करारा जवाब देना होगा। दरअसल इस समय पाकिस्तान अपने कच्चे वाले जम्मू-कश्मीर में चल रहे आजादी के आंदोलन से भी जूझ रहा है। यहां भी उसने निर्ममता बरतते हुए सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों को भूतने का काम हाल ही में किया है। पाक की ये हरकतें इसलिए भी बरकरार हैं, क्योंकि ईरान हमले में उलझा अमेरिका उसकी पीठ थपथपाने में लगा है। ऐसे में भारत को अनेक कूटनीतिक कदम उठाकर पाकिस्तान को विवश करना पड़ रहा है। अब जाकर उसे कश्मीर मुद्दे पर

अमेरिका का दो टूक जवाब मिला है।

अनुच्छेद-370 हटने के बाद भी हालातों में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो इसका एक बड़ा कारण मजहबी कड़ता पर चोट नहीं कर पाना है। गोया, साफ है कि यह समस्या अब राजनैतिक व संवैधानिक नहीं रह गई है, बल्कि धार्मिक चरमपंथ के रूप में सामने आ रही है। इस हिंसक उन्माद का सोच पाकिस्तान से निर्यात आतंकवाद तो है ही, घाटी में कुकुरमुत्तों की तरह मस्जिदों और मंदिरों में फैला, वह शिक्षा का तंत्र भी है, जो आतंक की फसल बोने और उगाने का काम करता है। यही वजह है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, उनमें न तो अल्पसंख्यकों का जनसंख्यात्मक घनत्व बढ़ रहा है और न ही उन्हें नागरिक समानता के अधिकार मिल रहे हैं। कश्मीर में भी जिहादी चाहते हैं कि गैर-मुस्लिम या तो इस्लाम स्वीकार करें या फिर घाटी छोड़ जाएं।

मुस्लिमों की इस दोषपूर्ण मंशा को संविधान निर्माण के समय ही डॉ भीमराव अंबेडकर ने समझ लिया था। शेख अब्दुला ने जब जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने की मांग की तो अंबेडकर ने स्पष्ट लहजे में कहा था कि आप चाहते हो कि भारत कश्मीर की रक्षा करे, कश्मीरियों की आर्थिक सुरक्षा करे, कश्मीरियों को संपूर्ण भारत में समानता का अधिकार मिले, लेकिन भारत और अन्य भारतीयों को आप कश्मीर में कोई अधिकार देना नहीं चाहते? मैं देश का कानून मंत्री हूं और मैं अपने देश के साथ कोई अन्याय या विश्वासघात किसी भी हालत में नहीं कर सकता हूं। विडंबना देखिए कि मुस्लिम समाज देश में हर जगह बृहद हिंदू समाज के बीच अपने को

सुरक्षित पाता है, किंतु जहां कहीं भी हिंदू अल्पसंख्यक मुस्लिमों के बीच रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। बावजूद नेहरू के अनावश्यक दखल से कश्मीर को विशेष दर्जा मिल गया। इस भिन्नता का संकट देश बंटवारे से लेकर अब तक भुगत रहा है। यही वजह है कि इस बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू, बौद्ध, सिख और द्रष्टर शरणार्थी के रूप में जम्मू-कश्मीर में ही ठहर गए थे, उन्हें मौलिक अधिकार धारा-370 हटने के बाद मिल पाए हैं। इनकी संख्या करीब 70-80 लाख है, ये 56 शरणार्थी शिविरों में सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से महरूम रहते हुए बद से बदतर जिंदगी का अभिशाप धारा-370 हटने से पहले तक भोगते रहे हैं।

पहलगाम हमले के बाद जितने भी आतंकी हमले कश्मीर में हुए हैं, उनमें से ज्यादातर की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली थी। यह लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन है, जो लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों की आतंकी हरकतों को ही अंजाम देता है। भारतीय सेना ने कोटली अब्बास में जिस आतंकी शिविरों को तबाह किया किया था, इसमें 1500 आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया था। मुरीदके में जिस मरकज तैयबा को ध्वस्त किया गया था, यहां लश्कर का मुख्यालय माना जाता है। यहीं से मुंबई हमले का प्रमुख आतंकी अजमल कसाब ने प्रशिक्षण लिया था। इस जबाबी कार्यवाही के बाद भारत की कूटनीति अत्यंत सफल दिखाई दी थी, क्योंकि भारत का तत्काल अमेरिका, रूस और जापान ने खुलकर समर्थन दिया था। यह समर्थन मोदी ने वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए जो मुहिम चलाई हुई है, उसका परिणाम था। अतएव इसमें कोई दो राय नहीं कि सीमापार स्थित ठिकानों से आतंकी गतिविधियां संचालित करने वाले संगठनों के खिलाफ सेना और सुरक्षाबलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कश्मीर में आतंकी बने रहने का एक कारण यह भी है कि आतंकियों को मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम होने के कारण संरक्षण आसानी से मिल जाता है। यही कारण है कि रुक-रुककर आतंकी बिना किसी शोर-शराब के मुस्लिम आबादी के बीच घुसपैठ करके हिंदुओं के विरुद्ध लक्षित हिंसा को परिणाम में बदलने में सफल हो जाते हैं। ऐसे हमलों में निंदोष लोग ही मारे जाते हैं। अब अमेरिकी राजनयिक के कथन के बाद संभव है आतंकी हमलों पर अंकुश लगे?

## नजरिया

# गठबंधन या मजबूरी का बंधन?

अशोक भाटिया  
मोबाइल : 9221232130



उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक शाश्वत नियम रहा है-यहाँ दिल्ली का रास्ता तो तय होता है, लेकिन प्रांतीय स्वाभिमान और क्षेत्रीय क्षत्रपों की महत्वाकांक्षाओं के टकराव में बड़े-से बड़े राष्ट्रीय एजेंडे भी ध्वस्त हो जाते हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने देश के सबसे बड़े राज्य में राजनीतिक चमत्कार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के 'अजेय' थर की रफ्तार पर ब्रेक लगाया, तो देश भर के विपक्षी रणनीतिकारों को लगा कि उन्होंने भाजपा की चुनौती मशीनरी की अचूक काट ढूँढ ली है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी, जिसे 'यूपी के दो लड़के' कहकर प्रचारित किया गया, ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के एक नए सामाजिक समीकरण को जन्म दिया। इस समीकरण को जनता का भारी समर्थन मिला और गठबंधन ने राज्य की 80 में से 43 सीटों पर ऐतिहासिक विजय पताका फहराई। परंतु, राजनीति में जीत जितनी सुखद होती है, उसकी विरासत को संभालना और आगामी संघर्षों के लिए उसे अक्षुण्ण रखना उतना ही दुरुह कार्य होता है। आज, 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही, इस सफल गठबंधन की नींव हिलती हुई साफ दिखाई दे रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली के गलियारों तक यह चर्चा आम है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 'सब कुछ ठीक नहीं है'। यह दरार अब केवल बंद कमरों की बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर सार्वजनिक मंचों से लेकर सोशल मीडिया के अखाड़े तक खुलकर सामने आ रही है।

इस गहरे अविश्वास, जमीनी अंतर्विरोध और दोनों दलों के बीच जारी वर्चस्व की जंग का सबसे ताजा, ज्वलंत और चिंताजनक उदाहरण हाल ही में सहारनपुर में आयोजित 'दिशा' की आधिकारिक बैठक के दौरान देखने को मिला। जिला स्तर पर विकास कार्यों, प्रशासनिक तालमेल और स्थानीय जनसमस्याओं (विशेषकर एक नाले के निर्माण और विकास कार्यों की अनदेखी) की समीक्षा के लिए बुलाई गई इस उच्च स्तरीय बैठक में जो कुछ हुआ, उसने उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर एक बहुत बड़ा यश प्रश्न खड़ा कर दिया है। बैठक के दौरान कांग्रेस के कदावर सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक आशु मलिक के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते यह बहस विकास कार्यों के दायरे को लांचकर व्यक्तिगत आक्षेपों, सांगठनिक श्रेष्ठता की जंग और तू-तू-मैं-मैं के अमध्यस्थित स्तर पर पहुंच गई। दोनों नेताओं के बीच करीब सात से आठ मिनट तक चली इस तीखी जुबानी जंग का वीडियो कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो

गया। यद्यपि, राजनीति के तयशुदा व्याकरण के अनुसार, घटना के अगले ही दिन दोनों नेताओं और दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने भारी डेमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू कर दीं। यह बयान जारी किए गए कि यह महज जनप्रतिनिधियों के बीच स्थानीय विकास कार्यों को लेकर हुई एक सामान्य प्रशासनिक बहस थी और इसे राजनीतिक गठबंधन के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता अफ़स्री तरह जानते हैं कि सियासत में इस तरह के सार्वजनिक और तीखे टकराव कभी भी महज प्रशासनिक मतभेद नहीं होते। यह वाक्या उस ज्वालामुखी का एक छोटा सा विस्फोट है जो पिछले कई महीनों से दोनों पार्टियों के प्रांतीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिलों में सुलग रहा था। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव में शीर्ष स्तर पर जो अल्पसंख्यक और आपसी समझौता पार्टी के पास है, उसकी विरासत को संभालना और आगामी संघर्षों के लिए उसे अक्षुण्ण रखना उतना ही दुरुह कार्य होता है। आज, 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही, इस सफल गठबंधन की नींव हिलती हुई साफ दिखाई दे रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली के गलियारों तक यह चर्चा आम है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 'सब कुछ ठीक नहीं है'। यह दरार अब केवल बंद कमरों की बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर सार्वजनिक मंचों से लेकर सोशल मीडिया के अखाड़े तक खुलकर सामने आ रही है।

इस गहरे अविश्वास, जमीनी अंतर्विरोध और दोनों दलों के बीच जारी वर्चस्व की जंग का सबसे ताजा, ज्वलंत और चिंताजनक उदाहरण हाल ही में सहारनपुर में आयोजित 'दिशा' की आधिकारिक बैठक के दौरान देखने को मिला। जिला स्तर पर विकास कार्यों, प्रशासनिक तालमेल और स्थानीय जनसमस्याओं (विशेषकर एक नाले के निर्माण और विकास कार्यों की अनदेखी) की समीक्षा के लिए बुलाई गई इस उच्च स्तरीय बैठक में जो कुछ हुआ, उसने उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर एक बहुत बड़ा यश प्रश्न खड़ा कर दिया है। बैठक के दौरान कांग्रेस के कदावर सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक आशु मलिक के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते यह बहस विकास कार्यों के दायरे को लांचकर व्यक्तिगत आक्षेपों, सांगठनिक श्रेष्ठता की जंग और तू-तू-मैं-मैं के अमध्यस्थित स्तर पर पहुंच गई। दोनों नेताओं के बीच करीब सात से आठ मिनट तक चली इस तीखी जुबानी जंग का वीडियो कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गया। यद्यपि, राजनीति के तयशुदा व्याकरण के अनुसार, घटना के अगले ही दिन दोनों नेताओं और दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने भारी डेमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू कर दीं। यह बयान जारी किए गए कि यह महज जनप्रतिनिधियों के बीच स्थानीय विकास कार्यों को लेकर हुई एक सामान्य प्रशासनिक बहस थी और इसे राजनीतिक गठबंधन के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता अफ़स्री तरह जानते हैं कि सियासत में इस तरह के सार्वजनिक और तीखे टकराव कभी भी महज प्रशासनिक मतभेद नहीं होते। यह वाक्या उस ज्वालामुखी का एक छोटा सा विस्फोट है जो पिछले कई महीनों से दोनों पार्टियों के प्रांतीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिलों में सुलग रहा था। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव में शीर्ष स्तर पर जो अल्पसंख्यक और आपसी समझौता पार्टी के पास है, उसकी विरासत को संभालना और आगामी संघर्षों के लिए उसे अक्षुण्ण रखना उतना ही दुरुह कार्य होता है। आज, 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही, इस सफल गठबंधन की नींव हिलती हुई साफ दिखाई दे रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली के गलियारों तक यह चर्चा आम है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 'सब कुछ ठीक नहीं है'। यह दरार अब केवल बंद कमरों की बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर सार्वजनिक मंचों से लेकर सोशल मीडिया के अखाड़े तक खुलकर सामने आ रही है।

इस रार और अविश्वास की जड़ें केवल स्थानीय मुद्दों या किसी नाले के निर्माण तक सीमित नहीं हैं। इसकी असली वजह 2027 की चुनौती विसात पर अपनी-अपनी ताकत दिखाने और भविष्य की सरकार में अपनी हिस्सेदारी तय करने की एक सोची-समझी राजनीति का हिस्सा है। 2024 की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है। पार्टी के रणनीतिकार, नए सांगठनिक प्रभारी और प्रांतीय नेता अब राज्य में खुद को समाजवादी पार्टी के 'जूनियर पार्टनर' या 'पिछलगु' के रूप में देखने को कतई तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के भीतर से लगातार यह मांग उठ रही है और सार्वजनिक मंचों से यह बयान दिए जा रहे हैं कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक और बराबरी की हिस्सेदारी से कम पर कोई समझौता नहीं करेगी। परम में भीतर एक बड़ा धड़ा साफ तौर पर काम से कम 150 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहा है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर हुई वापसी, राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' और उनके द्वारा तैयार किए गए नैरेटिव के बिना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अकेले दम पर 37 सीटें मिलना किसी भी सूत्रत में संभव नहीं था। कांग्रेस का मानना है कि मुस्लिम और दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के बेहरे और कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष साख को देखकर इस गठबंधन की ओर आकर्षित हुआ था। इसलिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसका वाजिब हक मिलना ही चाहिए, क्योंकि

उनके बिना राज्य में भाजपा-विरोधी कोई भी सरकार नहीं बन सकती। इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी खुद को उत्तर प्रदेश में भाजपा-विरोधी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का 'बड़ा भाई' और एकमात्र वास्तविक विकल्प मानती है। अखिलेश यादव और उनके रणनीतिकारों का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर वास्तविक संगठन, समर्पित कैडर, बूथ मैनेजमेंट और सांगठनिक मशीनरी केवल और केवल समाजवादी पार्टी के पास है। वोटों के इस आंतरिक ध्रुवीकरण और वर्चस्व की मूक जंग में सबसे बड़ा पेंच मुस्लिम और दलित मतदाताओं की भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर फंसा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस वर्ग ने बिना किसी दुविधा के, बेहद समझदारी से भाजपा को हराने के लिए एकमुश्त इस गठबंधन के पक्ष में मतदान किया था। परंतु अब, कांग्रेस को यह साफ दिखाई दे रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय और गैर-जाटव दलित मतदाता दोबारा अपने पुराने और पारंपरिक घर यानी कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इसी मुस्लिम-दलित-सवर्ण गठजोड़ के पुराने फॉर्मूले को पुनर्जीवित कर अपने वाला प्रतिद्वंद्वी ज्यादा मान रहे हैं। इस रार और अविश्वास की जड़ें केवल स्थानीय मुद्दों या किसी नाले के निर्माण तक सीमित नहीं हैं। इसकी असली वजह 2027 की चुनौती विसात पर अपनी-अपनी ताकत दिखाने और भविष्य की सरकार में अपनी हिस्सेदारी तय करने की एक सोची-समझी राजनीति का हिस्सा है। 2024 की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है। पार्टी के रणनीतिकार, नए सांगठनिक प्रभारी और प्रांतीय नेता अब राज्य में खुद को समाजवादी पार्टी के 'जूनियर पार्टनर' या 'पिछलगु' के रूप में देखने को कतई तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के भीतर से लगातार यह मांग उठ रही है और सार्वजनिक मंचों से यह बयान दिए जा रहे हैं कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक और बराबरी की हिस्सेदारी से कम पर कोई समझौता नहीं करेगी। परम में भीतर एक बड़ा धड़ा साफ तौर पर काम से कम 150 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहा है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर हुई वापसी, राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' और उनके द्वारा तैयार किए गए नैरेटिव के बिना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अकेले दम पर 37 सीटें मिलना किसी भी सूत्रत में संभव नहीं था। कांग्रेस का मानना है कि मुस्लिम और दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के बेहरे और कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष साख को देखकर इस गठबंधन की ओर आकर्षित हुआ था। इसलिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसका वाजिब हक मिलना ही चाहिए, क्योंकि

उनके बिना राज्य में भाजपा-विरोधी कोई भी सरकार नहीं बन सकती। इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी खुद को उत्तर प्रदेश में भाजपा-विरोधी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का 'बड़ा भाई' और एकमात्र वास्तविक विकल्प मानती है। अखिलेश यादव और उनके रणनीतिकारों का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर वास्तविक संगठन, समर्पित कैडर, बूथ मैनेजमेंट और सांगठनिक मशीनरी केवल और केवल समाजवादी पार्टी के पास है। वोटों के इस आंतरिक ध्रुवीकरण और वर्चस्व की मूक जंग में सबसे बड़ा पेंच मुस्लिम और दलित मतदाताओं की भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर फंसा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस वर्ग ने बिना किसी दुविधा के, बेहद समझदारी से भाजपा को हराने के लिए एकमुश्त इस गठबंधन के पक्ष में मतदान किया था। परंतु अब, कांग्रेस को यह साफ दिखाई दे रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय और गैर-जाटव दलित मतदाता दोबारा अपने पुराने और पारंपरिक घर यानी कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इसी मुस्लिम-दलित-सवर्ण गठजोड़ के पुराने फॉर्मूले को पुनर्जीवित कर अपने वाला प्रतिद्वंद्वी ज्यादा मान रहे हैं। इस रार और अविश्वास की जड़ें केवल स्थानीय मुद्दों या किसी नाले के निर्माण तक सीमित नहीं हैं। इसकी असली वजह 2027 की चुनौती विसात पर अपनी-अपनी ताकत दिखाने और भविष्य की सरकार में अपनी हिस्सेदारी तय करने की एक सोची-समझी राजनीति का हिस्सा है। 2024 की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है। पार्टी के रणनीतिकार, नए सांगठनिक प्रभारी और प्रांतीय नेता अब राज्य में खुद को समाजवादी पार्टी के 'जूनियर पार्टनर' या 'पिछलगु' के रूप में देखने को कतई तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के भीतर से लगातार यह मांग उठ रही है और सार्वजनिक मंचों से यह बयान दिए जा रहे हैं कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक और बराबरी की हिस्सेदारी से कम पर कोई समझौता नहीं करेगी। परम में भीतर एक बड़ा धड़ा साफ तौर पर काम से कम 150 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहा है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर हुई वापसी, राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' और उनके द्वारा तैयार किए गए नैरेटिव के बिना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अकेले दम पर 37 सीटें मिलना किसी भी सूत्रत में संभव नहीं था। कांग्रेस का मानना है कि मुस्लिम और दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के बेहरे और कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष साख को देखकर इस गठबंधन की ओर आकर्षित हुआ था। इसलिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसका वाजिब हक मिलना ही चाहिए, क्योंकि

## महत्त्वपूर्ण

Printed & Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , 1st floor, Cantonment station Road, Bengaluru-51and printed at Dinasadur Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekanth Parashar.** ("Responsible for selection of news under PRB Act). Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वरीकृत, टैंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादकों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रण एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरादाई नहीं बना सकता। - दक्षिण भारत राष्ट्रमत







